ऑल यूनियन्स एंड एसोसिएशन्स ऑफ बीएसएनएल (AUAB)

जिला शाखा .....

दिनांक 14.02.2019

प्रेस विज्ञप्ति

सादर प्रकाशनार्थ —

बीएसएनएल के कर्मचारी अधिकारी 18 फरवरी 2019 से तीन दिन हड़ताल पर रहेंगे— अपनी जायज मांगों के निराकरण की मांग के साथ साथ सरकार की कॉर्पोरेट परस्त और कर्मचारी विरोधी नीतियों का कर रहे हैं विरोध

बीएसएनएल के लगभग 1 लाख 75 हजार कर्मचारी अधिकारी लंबे समय से सरकार की कॉर्पोरेट परस्त और कर्मचारी विरोधी, पीएसयू विरोधी और जनविरोधी नीतियों का विरोध करते हुए अपनी जायज मांगों के निराकरण के लिए बीएसएनएल मैनेजमेंट और सरकार के खिलाफ संघर्षरत है। वें कर्मचारियों और अधिकारियों के सभी प्रमुख संगठन "ऑल यूनियन्स एंड एसोसिएशन्स ऑफ बीएसएनएल (एयूएबी)" के मंच तले एकत्रित हो कर लगातार संघर्ष कर रहे हैं।

बीएसएनएल कर्मियों की मांगों में जहां तृतीय वेतन पुनरीक्षण (3rd पे रिवीजन), पेंशन पुनरीक्षण, द्वितीय पीआरसी के शेष मुद्दों का निराकरण जैसे मुद्दे शामिल हैं, वहीं कर्मचारी बीएसएनएल के वित्तीय उन्नयन के लिए भी चिंतित हैं। उन्होंने अपने मांगपत्र में बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम आवंटित करने और बीएसएनएल द्वारा भारत सरकार के अपने नियमों के तहत वास्तविक वेतन पर पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन का भुगतान जैसे मुद्दों को शामिल किया है। ज्ञातव्य है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की हठधर्मिता के चलते बीएसएनएल द्वारा वेतनमान के अधिकतम पर पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन का भुगतान करने से बीएसएनएल को, एक आकलन के अनुसार, लगभग रु 500 करोड़ की सालाना चपत लग रही है।

यह सर्व विदित है कि सरकार एशिया के सबसे धनाढ्य शख्स मुकेश अम्बानी की कंपनी जियो टेलीकॉम पर किस कदर मेहरबान है। अपनी कॉर्पोरेट परस्त और पीएसयू विरोधी नीतियों को सिंचित करते हुए सरकार अपनी ही कंपनी "बीएसएनएल" के उत्थान में सहयोग करने की बजाय उसे दूरसंचार क्षेत्र में गलाकाट स्पर्धा के माहौल में प्रतिस्पर्धा से बाहर करने में जुटी हुई है। कॉर्पोरेट्स सरकारी बैंकों को करोड़ों की चपत लगा कर खोखला कर चुके हैं किंतु सरकारी कंपनी बीएसएनएल को ऋण लेने हेतु अनुमति देने में सरकार अड़ंगेबाजी कर रही है। विस्तार के लिए जरूरी 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन बीएसएनएल को नही किया जा रहा है। बीएसएनएल को अपनी अनुपयोगी जमीनों और भवनों का व्यावसायिक उपयोग करने से वंचित किया जा रहा है। इसकी अनुमति मिलने से बीएसएनल को करोड़ों की आय प्राप्त हो सकती है। सरकार की इन नीतियों से त्रस्त कर्मी लगातार अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठन संयुक्त रूप से कई बार धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, रैली, मानव श्रृंखला, संचार भवन पर हल्ला बोल, सत्याग्रह आदि कर चुके हैं। किंतु सरकार तटस्थ है। स्वयं माननीय संचार राज्य मंत्री द्वारा लगभग एक वर्ष पूर्व दिए गए आश्वासनों का क्रियान्वयन न होने से एयूएबी ने 3 दिसंबर 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आव्हान किया था। इस हड़ताल की जबरदस्त तैयारियों के मद्दे नजर विचलित सरकार ने दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के माध्यम से एयूएबी के लीडर्स को चर्चा हेतु आमंत्रित किया। आनन फानन में, रविवार होने के बावजूद 2 दिसंबर 2018 को सेक्रेटरी डीओटी, सीएमडी, बीएसएनएल ने अपने अधिकारियों की फौज के साथ एयूएबी के लीडर्स के साथ मुद्दों पर लंबी चर्चा की। दूसरे दिन, ताबड़तोब माननीय संचार राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा की भी 3 दिसंबर 2018 को एयूएबी से वार्ता हुई और एक निश्चित समयावधि में मांगपत्र में शामिल मुद्दों के ठोस निराकरण का आश्वासन दिया गया। फलस्वरूप, एयूएबी ने अपनी हड़ताल को कुछ समय के लिए मुल्तवी किया। किन्तु मुद्दों का निराकरण अपेक्षानुरूप नही हुआ है।

सरकार के रवैये से क्षुब्ध हो कर एयूएबी ने संघर्ष को पुनर्जीवित करने के लिए रणनीति तय करने हेतु मीटिंग आहूत की। मीटिंग में संज्ञान लिया गया कि 3rd पे रिवीजन के निराकरण में कोई प्रगति नही हुई है। यह भी महसूस किया गया कि 4G स्पेक्ट्रम के मुद्दे पर भी नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा व्यवधान निर्मित किया गया है। पेंशन रिवीजन के मुद्दे पर भी माननीय संचार राज्य मंत्री के पेंशन रिवीजन को पे रिवीजन से पृथक करने के आश्वासन के बावजूद स्वयं DoT द्वारा अड़ंगेबाजी की जा रही है। मीटिंग में बीएसएनएल में व्याप्त चिंताजनक स्थिति और वित्तीय संकट पर भी गंभीरता से चिंतन किया गया। कंपनी, DoT द्वारा जानबूझ कर उत्पन्न अवरोधों की वजह से बैंक लोन लेने की स्थिति में भी नही है।

उपर्युक्त स्थिति पर चर्चा के साथ इस पर भी चिंतन किया गया कि दूरसंचार विभाग द्वारा बीएसएनएल के रिवाइवल के सारे रास्तों पर किस तरह से बाधा उत्पन्न की जा रही है और किस प्रकार से सरकार भी निजी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए बीएसएनएल को आगे बढ़ाने में किसी भी रूप में सहयोग नही कर रही है। मीटिंग में यह बात भी चर्चा में आई कि बीएसएनएल मैनेजमेंट ने अपनी खाली पड़ी जमीनों के प्रभावी उपयोग/लीज पर देने के लिए "भूमि प्रबंधन नीति" (लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी) डीओटी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की है। यदि यह पॉलिसी अनुमोदित हो जाती है, तो बीएसएनएल को अपनी खाली जमीनों को लीज/किराए पर देने से रु 7,000 करोड़ से रु 10,000 करोड़ तक सालाना आय हो सकती है। किंतु डीओटी द्वारा इस प्रस्ताव को भी जानबूझकर कर अवरोधित किया जा रहा है।

विचलित करने वाली आर्थिक स्थिति के बावजूद बीएसएनएल मैनेजमेंट ने बीएसएनएल के टॉवर्स के रखरखाव के लिए अत्यधिक दरों पर आउटसोर्स करने की योजना बनाई है, जिसके लिए प्रति वर्ष भारी भरकम राशि का भुगतान करना होगा। इसकी शुरुआत में ही **AUAB** इसका विरोध कर चुकी है। किन्तु बीएसएनएल मैनेजमेंट अपनी योजना को आगे बढ़ा रहा है। सभी जगह टॉवर्स का मेंटेनेंस बीएसएनएल के कर्मचारियों द्वारा ही किया जा रहा है और निश्चित रूप से, इस हेतु इतनी अधिक राशि खर्च करने की जरूरत नही है, विशेष रूप से ऐसे समय जब कंपनी भीषण वित्तीय संकट का सामना कर रही है।

उपर्युक्त सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, एयूएबी सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अब कर्मचारियों द्वारा संघर्ष की पुनः शुरुआत का सही वक्त आ गया है। सर्वानुमति से यह निर्णय लिया गया कि सभी एग्जीक्यूटिव्ज व नॉन एग्जीक्यूटिव्ज **18.02.2019** से तीन दिवसीय हड़ताल पर जाएंगे। साथ ही अपनी मांगों के लिए जन समर्थन हासिल करने हेतु **11.02.2019** से **5** दिन तक देश भर में नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जाएगी और **15.02.2019** को कर्मचारी परिवार के सदस्यों के साथ रैली भी निकलेंगे। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों से कर्मचारियों की मांगों, विशेष रूप से बीएसएनएल का रिवाइवल, हेतु समर्थन हासिल करने के लिए मुलाकात की जाएगी।

कर्मचारी संगठन इस तथ्य से भलीभांति वाकिफ हैं कि, चुनाव की घोषणा होते ही उनकी मांगें अधर में लटकना तय है। बीएसएनएल कर्मियों के समक्ष **"** अभी नही तो कभी नही **"** की स्थिति है। इसीलिए ऑल यूनियन्स एंड एसोसिएशन्स ऑफ बीएसएनएल इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। बीएसएनएल के कर्मचारी अपने जायज अधिकारों की प्राप्ति के लिए लामबंद हो चुके हैं और संघर्ष के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ भी। ऐसे में, बीएसएनएल कर्मियों की राष्ट्रव्यापी तीन दिवसीय हड़ताल जबरदस्त रूप से सफल होगी, यह तय है।

बीएसएनएल को बंद करने की चर्चा छेड कर सरकार ने कर्मचारियोंको ललकारा है, वें इसका करारा जवाब देंगे।

<u>विस्तृत मांगपत्र निम्नानुसार है</u> :–

<u>मांग पत्र (चार्टर ऑफ डिमांड्स)</u>

(1) **15%** फिटमेंट के साथ **3rd** पे रिवीजन का निराकरण ।

(2) बीएसएनएल मैनेजमेंट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार बीएसएनएल को **4G** स्पेक्ट्रम का आवंटन।

(3) माननीय संचार राज्य मंत्री द्वारा पेंशन रिवीजन को पे रिवीजन से पृथक करने के आश्वासन का क्रियान्वयन किया जाए। **01.01.2017** से बीएसएनएल रिटायरिज का पेंशन रिवीजन करें।

(4) गवर्नमेंट के नियम अनुसार बीएसएनएल द्वारा पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन का भुगतान।

(5) **2nd** पे रिवीजन कमिटी के शेष मुद्दों का निराकरण।

(6) बीएसएनएल की भूमि प्रबंधन नीति (**Land Management Policy**) का बगैर देरी किए शीघ्र अनुमोदन।

  अ) बीएसएनएल की स्थापना के समय लिए गए निर्णय अनुसार नाम परिवर्तन (**mutation**) की और सभी संपत्ति (**assets**) बीएसएनएल को स्थानांतरित करने की कार्यवाही त्वरित पूर्ण की जाए।

(7) बीएसएनएल की स्थापना के समय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार बीएसएनएल की वित्तीय जीवंतता सुनिश्चित करें।

  इ) बीएसएनएल के बैंक से ऋण लेने के लिए प्रस्ताव हेतु **"**लेटर ऑफ कम्फर्ट''जारी किया जाए।

  ब) बीएसएनएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए।

(8) बीएसएनएल के मोबाइल टॉवर्स का आउटसोर्सिंग के माध्यम से संचालन व रखरखाव का प्रस्ताव रद्द (**Scrap**) किया जाए।

भवदीय,

DS BSNLEU & Convenor, AUAB **DS NFTE BSNL & Chairman, AUAB**

DS SNEA **DS AIBSNLEA** **DS AIGETOA**